भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 373**

दिनांक 21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

## ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट

†373. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना की वर्तमान स्थिति और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर तमिलनाडु के कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र में, आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत शामिल की गई ग्राम पंचायतों की संख्या और योजना, लेखांकन, निगरानी तथा सेवा वितरण जैसे मुख्य पंचायत कार्यों में प्राप्त डिजिटलीकरण का विस्तार कितना है;

(घ) क्या अपर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण में कमियों और अन्य ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्मों के साथ अंतःक्रियाशीलता जैसे मुद्दों की सूचना मिली है;

(ङ) यदि हां, तो डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और परियोजना के लंबित घटकों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और देश में इसके पूर्ण कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है; और

(च) क्या सरकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी और नागरिक शिकायत निवारण प्रणालियों को एकीकृत करके इस योजना को और मजबूत करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

## उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

**(क) और (ग)** पंचायती राज मंत्रालय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के कामकाज में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और जवाबदेही को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय ने इस परियोजना के तहत विभिन्न ऐप विकसित किए हैं, जिसमें ईग्रामस्वराज और ऑडिटऑनलाइन शामिल हैं। पंचायत शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए इन्हें सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है।

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत विकसित ई-ग्राम स्वराज और ऑडिटऑनलाइन ऐप ने शुरू से अंत तक (end-to-end) डिजिटल शासन को सक्षम बनाकर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ई-ग्रामस्वराज एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंचायत गतिविधियों की योजना, बजटन, लेखांकन और निगरानी की सुविधा प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता, कार्यकुशलता और कार्यों एवं निधि के उपयोग की वास्तविक समय में ट्रैकिंग करने में सुधार होता है। ऑडिटऑनलाइन पंचायत के खातों की ऑनलाइन लेखापरीक्षा को संभव बनाता है, जिससे समयबद्ध और मानकीकृत लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, बेहतर वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। साथ ही इन प्लेटफॉर्म ने पीआरआई को डेटा-आधारित निर्णय लेने, बेहतर रिकॉर्ड रखने, बेहतर वित्तीय प्रबंधन और ग्रामीण स्थानीय शासन में अधिक पारदर्शिता बढ़ाने में मदद की है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने ई-पंचायत एमएमपी के तहत कई अन्य ऐप भी विकसित किए हैं। मेरी पंचायत ऐप नागरिकों को पंचायत योजना, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराता है। पंचायत निर्णय ग्राम सभा की बैठकों के पारदर्शी संचालन और प्रबंधन को सुगम बनाता है। साथ ही, मंत्रालय ने 'सभासार' (SabhaSaar) लॉन्च किया है, जो ग्राम सभा और पंचायत की बैठकों के वॉयस-टू-टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन और सारांश के लिए एआई-आधारित प्लेटफॉर्म है, ताकि कार्यवाही का सटीक दस्तावेजीकरण सुनिश्चित हो सके। वर्तमान तिथि तक, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में कुल 2,58,730 ग्राम पंचायतों और समकक्षों में से, 2,55,251 ग्राम पंचायतें और समकक्ष (98.65%) ने ई-ग्राम स्वराज पर अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) अपलोड की है और 2,45,839 ग्राम पंचायतें और समकक्ष (95%) ने ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से ₹ 57,337 करोड़ धनराशि का भुगतान किया है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा अवधि 2024-25 के लिए, 2,33,743 जीपी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है।

**(ख)** ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (MMP) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निधि जारी नहीं की जा रही है। ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के तहत, ई-पंचायत ऐप के रखरखाव के लिए केंद्रीय स्तर पर सहायता हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (NICSI) को निधि जारी की जा रही है। पिछले पांच वर्षों के दौरान ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के तहत जारी की गई निधि इस प्रकार है।

राशि करोड़ में

| वर्ष | बजट आकलन | संशोधित आकलन | वास्तविक |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | 20.00 | 11.71 | 11.71 |
| 2022-23 | 20.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2023-24 | 20.00 | 16.28 | 16.03 |
| 2024-25 | 90.17 | 34.00 | 13.47 |
| 2025-26 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |

**(घ) और (ङ)** जी हाँ, ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं एवं अन्य ई-गवर्नेंस प्लेटफार्मों के साथ आपसी समन्वय जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत हितधारकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों, डिजिटल ऐप में निरंतर वृद्धि, पंचायतों को सहायता प्रदान करने और ई-ग्राम स्वराज को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), भाषिणी, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और बीएसएनएल जैसे सरकारी प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण करने सहित कई उपाय किए हैं। मंत्रालय अपने ऐप की समय-समय पर सुरक्षा लेखापरीक्षा भी करता है और प्लेटफ़ॉर्म की डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता और प्लेटफार्मों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए भूमिका-आधारित पहुंच नियंत्रण (रोल-बेस्ड एक्सेस कंट्रोल), सुरक्षित प्रमाणीकरण प्रणाली और डेटा बैकअप प्रोटोकॉल लागू करता है।

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय में की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय नियमित रूप से उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के आधार पर ऐप को अपग्रेड करता है और नई कार्यक्षमताएँ पेश करता है। तदनुसार, परियोजना को पूरा करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

**(च)** पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज संस्थाओं में डिजिटल शासन को मज़बूत बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से, मंत्रालय ने 'सभासार' (SabhaSaar) लॉन्च किया है। यह एआई-आधारित प्लेटफ़ॉर्म 'भाषिणी' (BHASHINI) के साथ जुड़ा हुआ है, ताकि ग्राम सभा की कार्यवाही का कई भाषाओं में ट्रांसक्रिप्शन, अनुवाद और सारांश तैयार किया जा सके। इससे पारदर्शिता, सुलभता और अभिलेखों के प्रबंधन में सुधार हो।

मंत्रालय कार्यात्मक आवश्यकताओं और तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर बेहतर निगरानी, निर्णय सहायता और नागरिक-केंद्रित सेवा प्रदायगी सहित ई-पंचायत पारिस्थितिकी तंत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है।

*****